

महंत परिचन दास

बनाम

बिहार राज्य बोर्ड धार्मिक न्यास और अन्य

6 नवंबर, 1979

[आर.एस. सरकारिया और ओ.चिनाप्पा रेड्डी, न्यायाधीशगण]

बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 1) – सार्वजनिक या निजी प्रकृति का न्यास – परीक्षण।

अपीलार्थी (वादी) वर्तमान महंत ने यह घोषणा करने के लिए एक मुकदमा दायर किया कि वाद-अनुसूची संपत्तियां उनकी निजी संपत्ति थीं और बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1951 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए धार्मिक या सार्वजनिक प्रकृति का कोई न्यास नहीं था। वाद में यह तर्क दिया गया कि एक जी ने गांव में अपनी जमीन पर एक मंदिर का निर्माण किया, देवताओं की स्थापना की, अपनी मृत्यु तक पूजा और राज-भोग किया। जनता को मूर्तियों से कोई सरोकार नहीं था और उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र बैरागी बन गया। उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के अलावा उनके बेटे ने अन्य संपत्तियां भी अर्जित कीं। बेटे की मृत्यु के बाद उनका चेला महंत बन गया। प्रत्येक उत्तराधिकारी महंत का उत्तराधिकारी उसका चेला होता था। संपत्तियां संबंधित महंतों द्वारा अपने नाम पर अर्जित की गईं और उन्हें उनकी निजी संपत्तियों के रूप में माना गया। महंतों में से एक ने पास के गांव में एक मंदिर का निर्माण किया जहां उन्होंने देवताओं को स्थापित किया और पूजा और राज-भोग लगाया। दावा किया गया कि मंदिर और संपत्तियां महंत की निजी संपत्ति थीं और जनता का उनमें कोई हित या अधिकार नहीं था। इस मुकदमे का प्रतिवादी नंबर 1 ने यह कहते हुए विरोध किया कि मंदिर और संपत्तियां महंत की निजी संपत्ति नहीं थीं और वे एक हिंदू धार्मिक न्यास की थीं, जिस पर बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1951 के प्रावधान लागू थे। विचारण न्यायालय ने वाद को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी डिक्री की पुष्टि की गई।

इस न्यायालय में की गई अपील में सवाल यह था कि क्या वाद-अनुसूची सम्पत्तियाँ ऐसी सम्पत्तियाँ थीं जिनके संबंध में सार्वजनिक या धार्मिक प्रकृति का न्यास था ताकि बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1951 के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके।

अभिनिर्धारित किया : 1. उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि न्यास सार्वजनिक प्रकृति का था। [1130 बी]

2. यह तथ्य कि जनता के सदस्यों को बिना किसी बाधा के मंदिर में जाने की अनुमति दी गई थी, ऐसी परिस्थिति नहीं हो सकती जो अपने आप में निर्णायक रूप से स्थापित हो कि जनता द्वारा मंदिर के उपयोग के अधिकार के तत्व के अभाव में मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर था। इसके विपरीत, उस समय महंत द्वारा मंदिर की संपत्तियों का मुफ्त उपयोग, जब वह मंदिर और उसकी संपत्तियों का एकमात्र प्रबंधक था, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर नहीं था। [1129 ई]

3. किसी न्यास के चरित्र को निर्धारित करने के लिए कोई सरल या निर्णायक तथ्यात्मक परीक्षण नहीं हो सकता है। परिस्थितियों की समग्रता और उनके प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए। [1129 एफ]

वर्तमान मामले में न केवल जनता को मंदिर में निःशुल्क प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन वे संस्था में बहुत अधिक रुचि दिखा रहे थे क्योंकि कई ग्रामीणों ने इसे भूमि दान में दी थी, एक ऐसी परिस्थिति जो आम तौर पर संस्था के सार्वजनिक होने की प्रकृति के अनुरूप होती है न कि निजी। [1129 एफ]

4. मंदिर की स्थिति यह निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण परिस्थिति होगी कि यह निजी था या सार्वजनिक। [1129 जी]

देवकी नंदन बनाम मुरलीधर [1956] एस.सी.आर. 756 संदर्भित

तत्काल मामले में उच्च न्यायालय ने बताया था कि गाँव के बाहर दो गाँवों के बीच खुली भूमि पर मंदिर का निर्माण किया गया था, ताकि दोनों गाँवों के ग्रामीणों के लिए सुविधाजनक हो। इसका निर्माण एक ऊँचे चबूतरे पर किया गया था और इसके चारों ओर पर्याप्त जगह के साथ सभी तरफ खुला था, ताकि दो गाँवों से बड़ी संख्या में ग्रामीणों को आकर्षित किया जा सके और समायोजित किया जा सके। यह इंगित करता है कि न्यास सार्वजनिक प्रकृति का था। [1129 एच-1130 ए]

5. जनता के सदस्यों द्वारा संस्था को भूमि का दान और जनता के लिए स्वतंत्र रूप से सुलभ और सुविधाजनक स्थान पर मंदिर का स्थान ऐसी परिस्थितियाँ थीं जो इंगित करती थीं कि न्यास सार्वजनिक प्रकृति का था। [1130 बी]

बिहार राज्य बोर्ड धार्मिक न्यास, पटना बनाम महंत श्री बिसेश्वर दास, [1971] 3 एस.सी.आर. 680, विशिष्ट।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2582/1969

पटना उच्च न्यायालय द्वारा अपील में मूल डिक्री संख्या 50/57 में पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 12-12-1961 से उत्पन्न।

बी. पी. सिंह, अपीलार्थी की ओर से।

डी. गोबर्धन, प्रतिवादी संख्या 1-2 की ओर से।

यू. पी. सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया -

चिनाप्पा रेड्डी, न्यायाधिपति. -

इस अपील में विचार करने के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या वाद-अनुसूची संपत्तियाँ उस क्षेत्र की संपत्तियाँ हैं जिनमें सार्वजनिक या धार्मिक प्रकृति का न्यास है ताकि बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम (1951 का अधिनियम I) के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके। वादी-अपीलकर्ता ने वाद दायर किया जिसमें यह घोषणा करने की अपील की गई कि संपत्तियाँ उसकी निजी संपत्ति थीं और इसमें कोई धार्मिक या सार्वजनिक प्रकृति का न्यास नहीं था ताकि बिहार अधिनियम I ऑफ़ 1951 के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके। उनका मामला, जैसा कि वाद में बताया गया है, यह था कि एक गुरदयाल सिंह ने एक मंदिर का निर्माण डुमरी गाँव में अपनी ज़मीन पर किया और रामजी, लक्ष्मणजी और सीताजी देवताओं को मंदिर में स्थापित किया। वह अपनी मृत्यु तक पूजा और राज-भोग करता था। जनता को मूर्तियों से कोई सरोकार नहीं था। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र गुलाब सिंह ने उसका स्थान लिया जो गुलाब दास का नाम धारण करते हुए बैरागी बन गए। गुरदयाल सिंह द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के अलावा, गुलाब दास ने अन्य संपत्तियाँ भी अर्जित कीं। उसकी मृत्यु पर उसके चेला ब्रह्मदास ने उनका स्थान लिया जिसके बदले में उसके चेला द्वारिका दास ने उसका स्थान लिया। प्रत्येक उत्तराधिकारी महंत के बाद उसके चेला ने पदभार संभाला, वर्तमान महंत वादी-अपीलार्थी हैं। संबंधित महंतों द्वारा अपने-अपने नामों पर संपत्तियों का अधिग्रहण किया जाता था और उन्हें हमेशा उनकी व्यक्तिगत संपत्तियों के रूप में माना जाता था। ब्रह्मदास ने मौदचिन गाँव में एक मंदिर का निर्माण किया जहाँ उन्होंने रामजी, लक्ष्मणजी और सीताजी के देवताओं को स्थापित किया और

पूजा और राज-भोग किया। मंदिर और संपत्तियाँ महंत की निजी संपत्तियाँ थीं और जनता का उनमें कोई हित या अधिकार नहीं था। इस वाद का विरोध बिहार राज्य धार्मिक न्यास मंडल और अन्य लोगों ने किया, जिन्होंने तर्क दिया कि मंदिर और संपत्तियाँ महंत की निजी संपत्तियाँ नहीं हैं और वे हिंदू धार्मिक न्यासों से संबंधित हैं, जिन पर बिहार धार्मिक न्यास अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। इस वाद को मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त उप न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था और पटना उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गई।

अपीलार्थी-वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी.सिंह ने विभिन्न साक्ष्य संबंधी मामलों पर उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए कई निष्कर्षों को स्वीकार किया। और तर्क दिया कि उन निष्कर्षों पर भी यह नहीं माना जा सकता कि संपत्तियाँ किसी धार्मिक या सार्वजनिक प्रकृति के न्यास की थीं। उन्होंने हमारा ध्यान बिहार राज्य बोर्ड धार्मिक न्यास, पटना बनाम महंत श्री बिशेश्वर दास ⁽¹⁾ मामले में इस न्यायालय के फैसले की ओर आकर्षित किया और कहा कि लगभग समान तथ्यों पर उस मामले में यह माना गया था कि धार्मिक या सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कोई न्यास नहीं था।

बिहार राज्य बोर्ड धार्मिक न्यास, पटना बनाम महंत श्री बिशेश्वर दास, ⁽¹⁾ में इस न्यायालय द्वारा संक्षेप में उच्च न्यायालय द्वारा पाए गए तथ्य थे:

"(1) कि मंदिर का निर्माण गैबी रामदास जी ने किया था और यह वही था जिसने उसमें देवताओं को स्थापित किया;

(2) कि उनके चेल द्वारा उन्हें महंत के लिए उत्तराधिकारी बनाया गया था, और उसके बाद गुरु से लेकर चेला तक महंत के लिए उत्तराधिकार किया गया था;

(3) कि उत्तराधिकारी की नियुक्ति गुरु से लेकर चेला तक की रही है, सत्ता में बैठे महंत ने अपने चेलों और जनता के सदस्यों में से अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति या नामांकन करने के लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाई है;

(4) कि संपत्तियों को हमेशा महंतों के नाम पर स्वामी के रूप में दर्ज किया गया है न कि डी रजिस्ट्रारों, खेवटों और खातियों में देवताओं के नाम पर;

(5) महंतों का अस्थल और संपूर्ण संपत्तियों पर कब्जा और प्रबंधन रहा है;

(6) कि महंतों ने समय-समय पर मालिक के रूप में अपने नाम पर संपत्ति अर्जित की, न कि किसी देवता या अस्थल के नाम पर, किसी भी समय किसी की

आपत्ति के बिना, और उनमें से कुछ को बिक्री, बंधक, पट्टे आदि के कार्यों के माध्यम से निपटाया।”

इस न्यायालय के समक्ष यह साबित करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों पर निर्भरता रखी गई थी कि संपत्तियां धार्मिक न्यास या सार्वजनिक उद्देश्य से प्रभावित थीं।

“(1) यह तथ्य कि महंत वैष्णव बैरागी थे जो जीवन भर ब्रह्मचारी रहे;

(2) यह कि साधुओं और अन्य लोगों को जब वे मंदिर गए भोजन और आश्रय दिया गया था;

(3) यह कि त्योहारों और अन्य महत्वपूर्ण हिंदू तिथियों का उपयोग जश्न मनाने के लिए किया जाता था;

(4) कि जनता के सदस्य मंदिर में बिना किसी बाधा के और अधिकार के दर्शन के लिए आए;

(5) कि कर्मों और वसीयतों में, जिसके तहत शासन करने वाले महंतों ने अपने उत्तराधिकारियों को नियुक्त या नामांकित किया था, संपत्तियों को अस्थल से संबंधित बताया गया था, और यह कि मंदिर अस्थल का प्रमुख हिस्सा था और पीठासीन की सेवा और पूजा के लिए बनाए रखा गया था। उनमें स्थापित देवता, संपत्तियाँ मंदिर की थीं, और इसलिए, वे धार्मिक और धर्मार्थ चरित्र के लिए एक न्यास की संपत्तियाँ थीं।

(6) मूर्तियों को आंशिक रूप से एक चौकी पर स्थापित किया गया था और मंदिर का निर्माण महंत के आवासीय क्वार्टर से अलग जमीन पर किया गया था।”

इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यास के चरित्र के साथ समान रूप से सुसंगत परिस्थितियों में से प्रत्येक सार्वजनिक या वात है और न्यास की सार्वजनिक प्रकृति को स्थापित करने की जिम्मेदारी बिहार राज्य धार्मिक बोर्ड पर नहीं थी।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों का उल्लेख करना आवश्यक है। उच्च न्यायालय ने पाया कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि मठ के संस्थापक कौन थे और मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। [यह भी

पाया गया कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि डुमरी गांव में मंदिर का निर्माण गुरदयाल सिंह की जमीन पर किया गया था, या मौदह गांव में मंदिर का निर्माण ब्रह्मदास की जमीन पर किया गया था। यह पाया गया कि विभिन्न महंतों द्वारा कई संपत्तियों को मूर्तियों के नाम के बजाय अपने नाम पर अर्जित किया गया था, लेकिन संपत्तियों का अधिग्रहण अस्थल या मठ के उद्देश्यों के लिए किया गया था। यह भी पाया गया कि डुमरी के ग्रामीणों द्वारा समय-समय पर जमीन दान में दी गयी है। यह पाया गया कि महंतों ने मंदिरों की मरम्मत के लिए केबालाओं को निष्पादित किया था और इसी तरह गिरवी के कार्यों को निष्पादित किया था। यह पाया गया कि डुमरी और मौदाह गांवों के लोग बिना किसी रोक-टोक के मंदिर में आते थे और मठ इस तरह स्थित था कि डुमरी और हरपुर दोनों के ग्रामीणों की सुविधा के अनुरूप था। यह दो गांवों की सीमा पर स्थित था और एक निश्चित ऊंचाई पर एक चबूतरे पर था, जो चारों तरफ से खुला था और इसके चारों ओर काफी जगह थी। मठ के मंदिर में आगंतुकों के लिए जगह के साथ तीन दरवाजे थे। उच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि धार्मिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए भूमि को लगान मुक्त रखा गया था।

जैसा कि विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है, यह सत्य है कि कई परिस्थितियाँ तटस्थ हैं। तथ्य यह है कि जनता के सदस्यों को बिना किसी बाधा के मंदिर में जाने की इजाजत थी, यह एक ऐसी परिस्थिति नहीं हो सकती है जो अपने आप में यह निर्णायक रूप से स्थापित करेगी कि मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर था, क्योंकि मंदिर के उपयोगकर्ता में सार्वजनिक अधिकार के तत्व का अभाव था। इसके विपरीत महंत द्वारा मंदिर की संपत्तियों का उस समय मुफ्त उपयोग जब वह मंदिर और उसकी संपत्तियों का एकमात्र प्रबंधक था, जरूरी नहीं कि इससे यह निष्कर्ष निकले कि मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर नहीं था। जाहिर तौर पर किसी न्यास के चरित्र को निर्धारित करने के लिए कोई सरल या निर्णायक तथ्यात्मक परीक्षण नहीं हो सकता है। परिस्थितियों की समग्रता और उनके प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए। यहां हम न केवल यह पाते हैं कि जनता के सदस्यों को मंदिर में निःशुल्क प्रवेश की अनुमति थी, बल्कि वे इस संस्था में बहुत अधिक रुचि दिखा रहे थे जैसा कि इस परिस्थिति से पता चलता है कि कई ग्रामीणों ने इसे भूमि दान में दी थी, एक ऐसी स्थिति जो सामान्यतः होती संस्था की प्रकृति सार्वजनिक होने के अनुरूप है न कि निजी होने की। फिर, जैसा कि वेंकटराम अय्यर, न्यायाधिपति ने देवकी नंदन बनाम मुरलीधर में बताया, मंदिर की स्थिति यह निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण परिस्थिति होगी कि यह निजी था या सार्वजनिक। उच्च न्यायालय ने कहा है कि मंदिर का निर्माण गांव के बाहर डुमरी और हरपुर गांवों के बीच खुली जमीन पर किया गया था ताकि दोनों गांवों के ग्रामीणों को सुविधा हो। इसका निर्माण एक ऊँचे मंच पर किया गया था और यह चारों ओर से खुला था और इसके चारों ओर बड़ी संख्या में लोगों को समायोजित करने के लिए काफी जगह थी। जाहिर है

कि मंदिर की स्थापना और निर्माण इसलिए किया गया था ताकि दोनों गांवों के बड़ी संख्या में ग्रामीणों को आकर्षित किया जा सके और समायोजित किया जा सके। जनता के सदस्यों द्वारा संस्था को भूमि का दान और जनता के लिए स्वतंत्र रूप से सुलभ और सुविधाजनक स्थान पर मंदिर का स्थान ऐसी परिस्थितियाँ थीं जो बिहार राज्य बोर्ड धार्मिक न्यास, पटना बनाम महंत श्री बिशेश्वर दास (सुप्रा) मामले में अनुपस्थित थीं। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि, इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि यह एक सार्वजनिक प्रकृति का न्यास था। अतः अपील को जुर्माने सहित खारिज किया जाता है।

एनवीके.

अपील खारिज की गई।

(1) [1971] 3 एस.सी.आर. 680, 686, 687

(1) [1956] एस.सी.आर 756

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक श्री विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

* * * * *